

अभियान } 45 हजार यूजी सीटों के मुकाबले 12 हजार पीजी सीटें
एचपीआई ने शुरू की 'सेव दी डॉक्टर' अभियान

पीजी सीटों की कमी के कारण विशेषज्ञों का आकाल : डॉ. शेट्टी

बैंगलूरु

bangaluru@patrika.com

एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एचपीआई) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने सोमवार को राष्ट्रव्यापी अभियान 'सेव दी डॉक्टर' की घोषणा की। एचपीआई इस अभियान के जरिए केन्द्र सरकार से देश में उपलब्ध मेडिकल के पीजी सीटों को यूजी सीटों के बराबर करने सहित अनिवार्य ग्रामीण पोस्टिंग को इंटर्नशिप और पीजी प्रशिक्षण में शामिल करने की मांग की है। एचपीआई ने दो से तीन लाख चिकित्सक और चिकित्सा विद्यार्थियों के इस अभियान से जुड़ने की उम्मीद जताई है। नारायण

हेल्थ समूह के संस्थापक और एचपीआई के ट्रेजरर डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी ने कहा कि देश में विशेषज्ञों की कमी का सबसे कारण है पीजी सीटों की कमी। दुख की बात है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जुड़ रहे देश के एमबीबीएस चिकित्सकों को इलाज करने के बजाय पीजी प्रवेश परीक्षा की तैयारियों में समय बिताना पड़ रहा है। हजारों ऐसे एमबीबीएस चिकित्सक हैं जिन्होंने डिग्री के बाद वर्षों से एक मरीज का इलाज नहीं किया है। डॉ. शेट्टी ने कहा कि अमरीकन में 19 हजार यूजी और 32 हजार पीजी सीटों के मुकाबले देश में 45,600 यूजी और 12 हजार पीजी की सीटें हैं। हर साल



बैंगलूरु में सोमवार को सेव डॉक्टर अभियान की शुरुआत के मौके पर प्रतिभागियों के साथ आईएमए के महासचिव डॉ. नरेन्द्र सैनी, डॉ. नरेश शेट्टी अभियान के संयोजक डॉ. नवनील एम. व अन्य।

करीब 40 हजार विद्यार्थी एमबीबीएस करने के बाद 12 हजार पीजी सीटों के लिए प्रतियोगिता करते हैं। देश में आयोजित विभिन्न पीजी प्रवेश परीक्षाओं में हर साल लाखों चिकित्सक शामिल होते हैं लेकिन 15 फीसदी से भी कम चिकित्सकों के लिए पीजी सीटें उपलब्ध हो पाती हैं। मौजूदा विशेषज्ञों के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे ही चलता रहा तो देश को विशेषज्ञ चिकित्सकों के आकाल का सामना करना पड़ेगा। आईएमए के महासचिव डॉ. नरेन्द्र सैनी ने

कहा कि अनिवार्य ग्रामीण पोस्टिंग ने समस्या और विकराल कर दी है। आईएमए ग्रामीण पोस्टिंग के खिलाफ नहीं है। पर मौजूदा हालात में इसे अनिवार्य करना न्यायसंगत नहीं है। विकल्प के तौर पर सरकार पीजी की पढ़ाई और इंटर्नशिप के दौरान छह महीने की ग्रामीण पोस्टिंग अनिवार्य कर सकती है। इसके अलावा हर मेडिकल अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान चार से पांच पदोन्नति का हकदार होता है। हर पदोन्नति के लिए एक साल की ग्रामीण पोस्टिंग अनिवार्य की जा सकती है। सरकार को समझना

चाहिए कि पैसों की कमी के कारण नहीं बल्कि विशेषज्ञों की कमी के कारण मरीजों को जान गंवानी पड़ रही है। हाल ही में जनता के दबाव के कारण ब्राजील के प्रधानमंत्री को क्यूबा से करीब छह हजार विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने देश बुलाना पड़ा था। हालात नहीं बदले तो वह दिन दूर नहीं जब देश को बाहर से विशेषज्ञ चिकित्सक मंगाने पड़ मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर एचपीआई के उपाध्यक्ष डॉ. अलेक्जेंडर थोमस, डॉ. नरेश शेट्टी अभियान के संयोजक डॉ. नवनील एम. उपस्थित थे।